Drishti IAS

करेंट अफेयर्स उत्तराखंड

अक्टूबर 2022 (संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501
Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

उत्तराखंड **3**

- मुख्यमंत्री ने डोईवाला में रानीपोखरी जाखन पुल का उद्घाटन किया 3
- उत्तराखंड में मोहाली की तर्ज़ पर बसेंगे अलग-अलग शहर 3
- स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में देहरादून नगर निगम को देश में 69वीं रैंक 4
- पर्यटन मंत्री ने किया जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ 4
- सूचना मंत्रालय ने निवृत्ति यादव को किया सम्मानित 5
- उत्तराखंड में ट्रैकरों की सुरक्षा के लिये बनेगी ट्रैकिंग नीति 5
- उत्तराखंड में बेसहारा बच्चों के लिये जल्द बनेगी पुनर्वास नीति 6
- उत्तराखंड में 'पीएम आवास योजना' की तर्ज़ पर संचालित होगी 'अटल आवास योजना' 6
- उत्तराखंड में बनेगा किसानों का डाटाबेस 7
- मुख्यमंत्री धामी ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवनिर्मित एफ.डी.ए. भवन व राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का किया लोकार्पण 7
- उत्तराखंड में बनने वाले नए रोपवे को सरकार की मिली मंज़ूरी 8
- उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का हुआ शुभारंभ 9
- निर्भया फंड से 10 पर्वतीय ज़िलों में बनेंगे महिला हॉस्टल 9
- जमरानी बांध निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुई शामिल 10
- पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल 'ट्रैक ऑफ द ईयर' घोषित 10
- प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया 11
- उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान 12
- उत्तराखंड में हिम तेंदुए छह साल में बढ़कर 121 हुए 12
- लैंसडौन का नाम बदलकर 'कालौं का डांडा' रखने का प्रस्ताव 13
- जमरानी बांध से पहले बनेंगे दो कॉफर बांध 13
- केंद्र ने उत्तराखंड के हवाले की एचएमटी की 45.33 एकड़ ज़मीन 14
- महिला क्षैतिज आरक्षण के अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार, राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद होगा लागू 14
- रक्षामंत्री ने चमोली-उत्तरकाशी में किया चार मोटर पुलों का वर्चुअल उद्घाटन 15
- उत्तराखंड में बदले जाएंगे गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम 15
- उत्तराखंड की 10 महिलाओं को मिलेगा नंदा देवी वीरता सम्मान 16

नोट :

उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने डोईवाला में रानीपोखरी जाखन पुल का उद्घाटन किया

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला में आयोजित एक कार्यक्रम में ऋषिकेश-भानियावाला मोटर मार्ग पर महत्त्वपूर्ण रानीपोखरी जाखन नदी और विधानसभा विकासनगर के अंतर्गत लंबरपुर लांघा मोटर मार्ग में शीतला नदी पर बने पुल का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि पिछले साल 2021 में पुल टूट जाने के बाद जनवरी 2022 में नया पुल बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कार्यदायी संस्था हिमालयन कंस्ट्रक्शन ने पुल निर्माण का कार्य 6 जुलाई को पूरा कर लिया।
- मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश, गढ़वाल आदि को राजधानी से जोड़ने वाला यह महत्त्वपूर्ण पुल है। पुल से स्थानीय जनता के अलावा सैलानियों को भी सुगमता होगी।
- केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि से जनपद के विकास खंड डोईवाला के अंतर्गत भानियावाला मार्ग मोटर मार्ग के 15किमी. में 280 मीटर स्पान के गर्डर सेतु का निर्माण किया गया है। रानीपोखरी पुल के लिये स्वीकृत लागत 18 करोड़ रुपए थी।
- मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल लाइन और दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड पर तेज़ी से काम चल रहा है। एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद दिल्ली और देहरादून के बीच की दूरी दो घंटे में पूरी हो जाएगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना की तर्ज़ पर मानसखंड कॉरिडोर को भी राज्य का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट तय कर इस पर कार्य शुरू कर दिया गया है। ऑल वेदर रोड से अब यात्रा सुगम व सुरक्षित हो गई है।

उत्तराखंड में मोहाली की तर्ज़ पर बसेंगे अलग-अलग शहर

चर्चा में क्यों ?

30 सितंबर, 2022 को उत्तराखंड के शहरी विकास एवं आवास के अपर मुख्य सचिव आनंदवर्द्धन ने चंडीगढ़ के उप नगर मोहाली की तर्ज़ पर उत्तराखंड में भी अब अलग-अलग शहर बसाए जाने की जानकारी दी।

प्रमुख बिंदु

- राज्य में अब अलग-अलग शहर बसाए जाने के संबंध में उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद ने निजी विकासकर्त्ताओं से आवेदन मांगे हैं। यह टाउनशिप तीन श्रेणियों में विकसित की जा सकती है।
- नेबरहुड- यह छोटी टाउनशिप होगी। मैदानी क्षेत्रों में छह हेक्टेयर से 20 हेक्टेयर और पर्वतीय क्षेत्रों में तीन हेक्टेयर से दस हेक्टेयर भूमि पर ही यह टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
- टाउनशिप- मैदानी क्षेत्रों में 20 से 40 हेक्टेयर भूमि पर और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 से 20 हेक्टेयर भूमि पर यह टाउनशिप विकसित की जा सकेगी।
- स्पेशल टाउनशिप- मैदानी क्षेत्रों में 40 हेक्टेयर से अधिक भूमि और पर्वतीय क्षेत्रों में 20 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर यह टाउनशिप विकसित की जाएगी।

नोट :

- उत्तराखंड सरकार की इस योजना का उदेश्य यह है कि पुराने शहरों का बोझ कम हो और नए शहरों में लोगों को अत्याधुनिक सुविधाएँ मिलें। सभी टाउनशिप की उत्तराखंड आवास एवं विकास परिषद निगरानी करेगा।
- सरकार ने इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिये टास्क फोर्स का गठन किया है। प्राप्त आवेदनों का सर्वेक्षण कराया जाएगा। विशेषज्ञ यह बताएंगे कि संबंधित ज़मीन पर टाउनशिप विकसित हो सकती है या नहीं। इसके बाद उस जगह का मास्टर प्लान तैयार होगा। विकासकर्त्ता को उस जगह पर सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध करानी होंगी।
- भू-उपयोग परिवर्तन से लेकर मास्टर प्लान, रेरा से पंजीकरण सहित तमाम सरकारी कामों में विकासकर्त्ता को परिषद से सहयोग मिलेगा, हालाँकि सरकारी शुल्क जमा कराने होंगे।
- मोहाली की तर्ज़ पर जो शहर बनेंगे, वहाँ स्कूल, कॉलेज से लेकर अस्पताल और खेल के मैदान तक की पूरी सुविधा होगी।
- मोहाली को जैसे सेक्टर में बाँटा गया है, वैसे ही उत्तराखंड के शहरों को भी सेक्टर में बाँटा जा सकेगा। इसमें विशेष क्षेत्र, जैसे- आईटी कंपनियों के लिये या अन्य रोज़गार देने वाली कंपनियों के लिये भी अलग से जगह सुरक्षित की जाएगी।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2022 में देहरादून नगर निगम को देश में 69वीं रैंक

चर्चा में क्यों ?

2 अक्टूबर, 2022 को देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के परिणामों की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड के निकायों में पिछली बार की अपेक्षा अच्छा प्रदर्शन करते हुए देहरादून नगर निगम ने देश में 69वीं रैंक प्राप्त की है।

प्रमुख बिंदु

- मेयर सुनील उनियाल गामा ने बताया कि स्वच्छता रैंकिंग में नगर निगम देहरादून का प्रदर्शन साल-दर-साल सुधर रहा है। बेहद सीमित संसाधनों के बाद भी देहरादून नगर निगम पिछली बार की तुलना में 13 अंकों की छलांग लगाते हुए उत्तराखंड के शहरों में भी प्रथम स्थान पर है।
- विदित है कि वर्ष 2021 में देहरादून की देशभर में 82वीं रैंक थी। अबकी बार 13 अंकों की छलांग लगाते हुए बेहतर प्रदर्शन किया। वर्ष 2019 से देहरादून नगर निगम लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। 2019 में देहरादून नगर निगम को देशभर में 384वाँ स्थान मिला था, जबकि वर्ष 2020 में 124वाँ, 2021 में 84वाँ और वर्ष 2022में 69वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- हिमालयी राज्यों में गारवेज फ्री सिटी में देहरादून नगर निगम देशभर में एकमात्र शहर रहा। पूरे हिमालयी राज्यों में केवल दून शहर ही ऐसा है, जो देशभर के गारवेज सिटी शहरों में शामिल हुआ है। देहरादून को इसमें तीन स्टार मिले हैं।

पर्यटन मंत्री ने किया जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

3 अक्टूबर, 2022 को प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट से हिमालय दर्शन सेवा का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। एक सप्ताह के ट्रायल के बाद हिमालय दर्शन सेवा का शुभारंभ किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री ने कहा कि इस हेली सेवा से जहाँ पर्यटकों को नजदीक से हिमालय के दर्शन करने को मिलेंगे। वहीं, प्रदेश की आर्थिकी में भी वृद्धि होगी और रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे।
- उन्होंने कहा कि जल्द ही जॉर्ज एवरेस्ट मसूरी में महान सर्वेयर जॉर्ज एवरेस्ट की स्मृति में संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा। इस संग्रहालय में भारतीय कार्टोग्राफी के पुरोधा स्वर्गीय नैन सिंह रावत और राधानाथ सिंकदर की प्रतिमाएँ स्थापित करने के साथ ही उनकी उपलब्धियों को रखा जाएगा।

नोट :

- पर्यटन मंत्री ने कहा कि एयर स्पोर्ट्स से जुड़ी अन्य कई आकर्षक गतिविधियाँ भी जॉर्ज एवरेस्ट से शुरू की जा रही हैं। इसके लिये पर्यटन विभाग ने ट्रायल के लिये एक प्रतिष्ठित कंपनी से अनुबंध भी किया है।
- उन्होंने बताया कि विश्व पर्यटन दिवस पर पर्यटन प्रेमियों के लिये आकर्षक फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी कॉन्टेस्ट का उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत पाँच विभिन्न श्रेणियों में फोटो एवं वीडियो ऑनलाइन आमंत्रित किये जा रहे हैं। इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से प्रकृति पर्यटन प्रेमियों को 25 लाख रुपए से अधिक के पुरस्कार प्रदान किये जाएंगे।

सूचना मंत्रालय ने निवृत्ति यादव को किया सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

5 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के निवृत्ति यादव को देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के पैतृक गाँव सैंण को गोद लेने व समाज के बेहतर कार्य करने के लिये केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- वर्तमान में निवृत्ति यादव डॉ. हरिवंशराय बच्चन प्रतिष्ठान के संस्थापक भी हैं। यह संस्था गाँव के बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया करवाने के साथ ही ग्रामीणों को स्वरोज़गार से जोड़ने का कार्य कर रही है। इसके लिये सैंण गाँव में महिलाओं के लिये सिलाई सेंटर व अन्य कई प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं।
- संस्था के इन्हीं कार्यों को देखते हुए निवृत्ति यादव को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस व गढ़वाल के सांसद तीरथ सिंह रावत की ओर से दिया गया है।
- वहीं, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र भाकर द्वारा निवृत्ति यादव को मुंबई क्षेत्र के सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में भी जिम्मेदारी दी गई। निवृत्ति यादव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्त्वाकांक्षी आदर्श ग्राम परियोजना-2014 से भी जुड़े हुए हैं।

उत्तराखंड में ट्रैकरों की सुरक्षा के लिये बनेगी ट्रैकिंग नीति

चर्चा में क्यों ?

6 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि प्रदेश में ऊँची चोटियों की चढ़ाई करने वाले ट्रैकरों और ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा के लिये पर्यटन विभाग के माध्यम से ट्रैकिंग नीति तैयार की जा रही है।

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि ट्रैकिंग नीति में प्रदेश में पर्वतारोहण करने वाले ट्रैकरों व ट्रैकिंग करने वाले पर्यटकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा।
- नीति के तहत सरकार की ओर से पर्वतारोहण दल के लीडर को सैटेलाइट फोन सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे पर्वतारोहण दल के किसी मुश्किल में फँसने या लापता होने की स्थिति में आसानी से लोकेशन का पता लग सकेगा।
- इसके अलावा पोर्टरों को प्रशिक्षण और अनुभव के आधार पर लाइसेंस देने के लिये नीति में प्रावधान किया जा रहा है।
- ट्रैकिंग के लिये प्रदेश में अभी कोई नीति नहीं है। ट्रैकिंग करने वाले पर्यटक बिना किसी सूचना के ही ट्रैक रूट पर निकल जाते हैं। कोई हादसा होने पर सरकार व प्रशासन के पास भी ट्रैकिंग दल का कोई ब्योरा नहीं रहता है।
- वर्ष 2003-04 में पर्वतारोहण के लिये गाइडलाइन बनाई गई थी, जो पेशेवर ट्रैकरों के लिये ही लागू थी। वर्तमान में सरकार का विशेष ध्यान साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर है, जिससे बाहरी क्षेत्रों के पर्यटक ट्रैकिंग के लिये उत्तराखंड आ रहे हैं।

नोट :

- गौरतलब है कि प्रदेश में हर साल देश दुनिया के पेशेवर ट्रैकरों के अलावा साहसिक पर्यटन में रुचि रखने वाले पर्यटक ट्रैकिंग के लिये आते हैं। कई बार पर्वतारोहण दल के साथ घटनाएँ हुई हैं। अब सरकार ट्रैकिंग के लिये आने वाले पर्यटकों और ट्रैकरों की सुरक्षा के लिये नीति बना रही है।

उत्तराखंड में बेसहारा बच्चों के लिये जल्द बनेगी पुनर्वास नीति

चर्चा में क्यों ?

10 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड की महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य में पहली बार स्ट्रीट चिल्ड्रेन (बेसहारा) पुनर्वास नीति 9 नवंबर से लागू की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने बताया कि सरकार की ओर से इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जिसे राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर) के अवसर पर लागू करने की तैयारी है।
- उन्होंने बताया कि राज्य में अनाथ और सड़कों पर बेसहारा घूम रहे बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिये पुनर्वास नीति का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री ने इस नीति का ड्राफ्ट बनाया है। नीति को अंतिम रूप देने के लिये सभी ज़िलों के ज़िलाधिकारियों एवं संबंधित अधिकारियों से सुझाव मांगे गए थे।
- विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सड़कों पर रहने वाले तीन तरह के बच्चे हैं। एक वह बच्चे हैं, जो अकेले रहते हैं। दूसरे अपने माता-पिता के साथ रहते हैं। तीसरे वह बच्चे हैं, जो दिनभर सड़क पर रहते हैं और दिन ढलते ही मलिन बस्तियों में चले जाते हैं। इस तरह के बच्चे न स्कूल में हैं, न परिवार में। अधिकतर बच्चे उत्तराखंड से बाहर के राज्यों के हैं।
- उन्होंने बताया कि खासतौर पर इस तरह के बच्चे देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल ज़िले में हैं। इन बच्चों के लिये नीति में आश्रय गृह बनाने की व्यवस्था की जा रही है।
- अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल देहरादून, हरिद्वार व हल्द्वानी में आश्रय गृह चल रहे हैं, जिन्हें आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाया जाएगा।
- नीति को लेकर कुछ ज़िलाधिकारियों का यह भी प्रस्ताव है कि दिन में इन बच्चों को आश्रय गृह में रखा जाए, जबकि शाम को वह अपने परिवार के साथ चले जाएँ।
- इस नीति में इन बच्चों की पढ़ाई-लिखाई के साथ ही उन्हें कौशल विकास से भी जोड़ने की तैयारी है।

उत्तराखंड में 'पीएम आवास योजना' की तर्ज़ पर संचालित होगी 'अटल आवास योजना'

चर्चा में क्यों ?

10 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के समाज कल्याण मंत्री चंदन रामदास ने राज्य में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिये 'अटल आवास योजना' को अब 'प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)' की तर्ज़ पर संचालित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।

प्रमुख बिंदु

- समाज कल्याण मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि पूर्व में बंद हो चुकी इस योजना में प्रति लाभार्थी भवन निर्माण के लिये दी जाने वाली 38 हज़ार रुपए की आर्थिक सहायता काफी कम थी, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना में 1.30 लाख रुपए की राशि देने का प्रवधान है।
- उन्होंने कहा कि अब इसी तर्ज़ पर अटल आवास योजना के संचालन का प्रस्ताव तैयार करने का यह विषय कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा।

नोट :

- कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से वर्तमान में वही लोग लाभान्वित हो रहे हैं, जिनका पाँच वर्ष पहले पंजीकरण हो चुका है। इस सबके मद्देनज़र गरीबों को राहत देने के लिये अटल आवास योजना को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है।
- विदित है कि राज्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पाँच निगम और इतने ही बोर्ड हैं। निगमों द्वारा दिये गए ऋण में से लगभग 20 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। इसे देखते हुए अब 'एकमुश्त समाधान योजना' लाई जा रही है, ताकि संबंधित व्यक्तियों को राहत मिलने के साथ ही निगमों को कम-से-कम मूलधन वापस मिल सके।

उत्तराखंड में बनेगा किसानों का डाटाबेस

चर्चा में क्यों ?

11 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड राज्य के देहरादून सचिवालय में केंद्र सरकार के चीफ नॉलेज ऑफिसर राजीव चावला की अध्यक्षता में राज्य में किसानों के भू-अभिलेख के संबंध में हुई बैठक में राज्य के अधिकारियों को किसानों का डाटाबेस तैयार करने के निर्देश दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- राजीव चावला ने केंद्र सरकार की ओर से विकसित एग्री स्टैक पोर्टल के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी कागज़ी प्रक्रिया के देने के लिये राज्य में किसानों का डाटाबेस तैयार किया जाएगा।
- इसके लिये प्रत्येक किसान को विशिष्ट पहचान (यूनिक आइडी) उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही, पोर्टल के लिये राज्य के समस्त किसानों के भू-अभिलेखों के सुधार के संबंध में प्रस्तुतीकरण देते हुए बताया कि एग्री स्टैक पोर्टल के तीन प्रमुख स्तंभ किसान डाटाबेस, भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र और फसल सर्वे डाटा हैं।
- उन्होंने बैठक में बताया कि उत्तराखंड में किसानों का अलग से डाटाबेस नहीं है। पीएम किसान योजना के आनॅलाइन पीएम किसान पोर्टल पर ही यह किसानों का डाटा उपलब्ध है।
- पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों का डाटा विभागीय डाटाबेस में एकीकृत किया जाएगा। यह कुल किसानों का लगभग 80 से 85 प्रतिशत होगा। राजस्व विभाग ऑनलाइन-राइट ऑफ रिकॉर्ड में प्रत्येक किसान के स्वामित्व की भूमि में बोई जाने वाली सभी मौसमी फसलों के क्षेत्रफल का विवरण दर्ज होगा।
- कृषि विभाग इस डाटा को अद्यतन कर उपयोग में लाएगा। इस टाइम सीरीज़ डाटा से भविष्य में फसलों के प्रत्येक माह संभावित अनुमान तैयार किये जा सकेंगे। फसलवार प्राप्त जानकारी का उपयोग किसान क्रेडिट कार्ड से फसली ऋण, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना व फसल विपणन का लाभ प्राप्त करने में किया जाएगा। इससे किसान को सत्यापित जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होगी।
- बैठक में बताया गया कि राज्य में ग्रामों के मानचित्रों को ऑनलाइन कराने के लिये राजस्व विभाग निविदा कर चुका है। पहले चरण में दो ज़िलों-अल्मोड़ा और पौड़ी के मानचित्रों को ऑनलाइन किया जाएगा, शेष ज़िलों के मानचित्रों को दो वर्ष में ऑनलाइन किया जाएगा।
- फसल सर्वे डाटा के लिये कृषि विभाग की ओर से देहरादून व चंपावत ज़िलों हेतु प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया गतिमान है। देहरादून व चंपावत के भू-राजस्व डाटा, सॉयल प्रोफाइलिंग के डाटा को उपयोग में लाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग से विभिन्न विभागीय डैशबोर्ड तैयार किये जाएंगे। अन्य ज़िलों के लिये राजस्व विभाग भू-संदर्भित ग्राम मानचित्र उपलब्ध कराने के बाद चरणबद्ध रूप से फसल सर्वे का कार्य कराएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवनिर्मित एफ.डी.ए. भवन व राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों ?

12 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सहस्त्रधारा रोड स्थित डांडा लखौड में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के नवनिर्मित एफ.डी.ए. भवन व राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के फार्मा सेक्टर के लिये औषधि नियंत्रण संगठन एवं राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ी पहल की जा रही है। इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को केंद्र में रखकर 56 करोड़ रुपए की लागत से एफ.डी.ए. भवन का निर्माण किया गया है।
- इसके अतिरिक्त 22 करोड़ रुपए की लागत से एफ.डी.ए. भवन में औषधि नमूनों की गुणवत्ता जाँचने हेतु राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है। इस प्रयोगशाला में वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार का प्रयास है कि राज्य में औषधि निर्माण और इस क्षेत्र में विस्तार की संभावनाओं को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाए। इसी के परिणामस्वरूप राज्य में औषधि निर्माण की ईकाइयाँ लगातार बढ़ रही हैं। राज्य में लगभग 300 औषधि निर्माता कंपनियाँ कार्य कर रही हैं। ये सभी इकाइयाँ अपने उत्पादन के ज़रिये हज़ारों लोगों को रोज़गार उपलब्ध करवा कर रही है।
- उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में प्रकृति प्रदत्त अनेक संपदाएँ हैं। उत्तराखंड आयुष, योग धर्म एवं संस्कृति की भूमि तो है ही, इसके अलावा अब उद्योगों की भूमि भी बन रही है।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा औषधि निर्माता कंपनियों को हर संभव मदद दी जाएगी। वर्ष 2025 में जब उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनाएगा, तब तक उत्तराखंड को उत्कृष्ट राज्य बनाने में फार्मा सेक्टर क्या योगदान दे सकता है, इस दिशा में ध्यान दिया जाएगा।
- राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में औषधि निर्माता कंपनियों को बढ़ावा देने के लिये लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। दवा कंपनियों को लाइसेंस लेने में दिक्कतें न हो इसके लिये ऑनलाईन प्रक्रिया अपनाई जा रही है।
- वर्ष 2024 तक राज्य को क्षय रोग मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ब्लड डोनेशन एवं संस्थागत प्रसव में उत्तराखंड श्रेष्ठ राज्यों में है।

उत्तराखंड में बनने वाले नए रोपवे को सरकार की मिली मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

13 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के वन एवं लोनिवि के प्रमुख सचिव आरके सुधांशु ने बताया कि राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने केदारनाथ सेंक्चुरी एरिया में रोपवे के निर्माण को स्वीकृति दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- आरके सुधांशु ने बताया कि केदारनाथ के लिये एक हज़ार करोड़ रुपए के खर्च वाली इस परियोजना को राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड से मंज़ूरी मिल गई है। रोपवे बन जाने के बाद राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
- उन्होंने बताया कि केदारनाथ सेंक्चुरी एरिया में रोपवे के निर्माण को स्वीकृति मिलने के साथ ही केदारनाथ के पैदल ट्रैक व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजना को भी बोर्ड द्वारा हरी झंडी मिल गई है।
- इन परियोजनाओं का निर्माण केंद्र सरकार की पर्वतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा, जिसके लिये कुल 26 हेक्टेयर ज़मीन अधिग्रहीत की जाएगी।
- केदारनाथ के लिये रोपवे बन जाने के बाद सोनप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा महज़ 30 मिनट में पूरी हो जाएगी। रोपवे की क्षमता प्रति घंटा पाँच हज़ार यात्रियों को ले जाने की होगी।
- इसके अलावा राष्ट्रीय वन्य जंतु बोर्ड ने रामबाड़ा से गरुड़चटी तक साढ़े पाँच किलोमीटर पैदल ट्रैक के निर्माण को भी मंज़ूरी दे दी है। यह मार्ग 2013 की आपदा में पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था।

नोट :

उत्तराखंड में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

16 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिये राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के लिये उत्तराखंड ने उच्च शिक्षा में इसका शुभारंभ कर दिया है।
- विदित है कि बाल वाटिका से प्रारंभिक शिक्षा में उत्तराखंड ने ही इसकी सबसे पहले शुरुआत की थी।
- उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड विद्वानों की भूमि है। इस देवभूमि से नई शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिये अभी अनेक विचार आएंगे। अब प्रयास करने होंगे कि आने वाले समय में शत-प्रतिशत बच्चे बाल वाटिकाओं में प्रवेश करें।
- उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मानवीय जीवन के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। शिक्षा के अलावा बच्चों के कौशल विकास, उनके व्यक्तित्व के विकास, भाषाई विकास एवं नैतिक मूल्यों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।
- केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को 3 साल से फॉर्मल एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत बाल वाटिका शुरू की गई।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किये जाने के दिशा में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रभावी एवं चरणबद्ध रूप से सकारात्मक कदम बढ़ाए गए हैं।
- नई शिक्षा नीति प्रधानमंत्री के नेतृत्व व मार्गदर्शन में तैयार की गई 21वीं सदी के नवीन, आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के नए आयाम खोलने वाली नीति है, जिसे देश के ख्यातिलब्ध शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया गया है और ये नए भारत की नई उम्मीदों नई आवश्यकताओं की पूर्ति का सशक्त माध्यम है।
- राज्य के विद्यालयी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि एनईपी 2020 के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में वर्तमान शैक्षणिक सत्र से प्रवेश शुरू कर दिये गए हैं। इसके लिये नई नीति के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किये गए हैं।
- विभागीय मंत्री ने बताया कि नई नीति के क्रियान्वयन के लिये राज्यस्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया तथा साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी और कैरिकुलम डिज़ाइन समिति गठित की गई, जिनकी विभिन्न स्तर पर कई दौर की बैठकों और पब्लिक डोमेन से मिले सुझावों के उपरांत पाठ्यक्रम तैयार किया गया। इस पाठ्यक्रम को सभी विश्वविद्यालयों की बीओएस, एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्युटिव कमेटी द्वारा अप्रूव्ड किया गया है ।
- उन्होंने बताया कि नई नीति के तहत छात्र-छात्राओं को चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का लाभ मिलेगा और अब वह अपने मनपसंद विषय एवं विश्वविद्यालय चुन सकेंगे।
- डॉ. रावत ने बताया कि नए पाठ्यक्रम रिसर्च, इनोवेशन और इंटरप्रेन्योरशिप बेस्ड होंगे। इसमें रोबोटिक्स जैसे एडवांस कोर्स रखे गए हैं। कोकैरिकुलम कोर्स के 6 सेमेस्टरों के प्रत्येक सेमेस्टर में भारतीय ज्ञान परंपरा, कम्युनिकेशन स्किल, इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट पैराडाइज ऑफ भगवद् गीता, योगा, विवेकानंद स्टडीज़, पर्सनली डेवलपमेंट, रामचरितमानस, ट्रेडिशनल नॉलेज, वैदिक साइंस और वैदिक गणित जैसे कोर्स भी रखे गए हैं।

निर्भया फंड से 10 पर्वतीय ज़िलों में बनेंगे महिला हॉस्टल

चर्चा में क्यों ?

17 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास सचिव एच.सी. सेमवाल ने बताया कि निर्भया फंड के परियोजना स्वीकृति बोर्ड की नई दिल्ली में हुई बैठक में उत्तराखंड के 10 पर्वतीय ज़िलों में महिला हॉस्टल के निर्माण के सुझाव को बोर्ड ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- एच.सी. सेमवाल ने बताया कि हरिद्वार, देहरादून व ऊधमसिंह नगर ज़िलों को छोड़ कर राज्य के शेष 10 पर्वतीय ज़िलों में इन हॉस्टल का निर्माण कामकाजी महिलाओं और अध्ययनरत् बालिकाओं को सुरक्षित व संरक्षित वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से निर्भया फंड से किया जाएगा।
- विदित है कि निर्भया फंड केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से संचालित किया जा रहा है।
- सेमवाल ने बैठक में बताया कि राज्य के पाँच ज़िलों- बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार व ऊधमसिंह नगर में निर्भया फंड से 2522 महिलाओं व बालिकाओं को आत्मरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा चुका है। साथ ही राज्य के लिये दीर्घकालिक योजना बनाने पर भी ज़ोर दिया जा रहा है।
- महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास सचिव ने कहा कि सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण में महिला व बाल विकास को केंद्र में रखना आवश्यक है। यदि पंचायतें महिला व बाल हितैषी बनेंगी तो इससे कई समस्याओं का स्वयं ही समाधान हो जाएगा।

जमरानी बांध निर्माण परियोजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में हुई शामिल

चर्चा में क्यों ?

18 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि जल संसाधन के केंद्रीय सचिव की अध्यक्षता एवं नीति आयोग व केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों की बैठक में जमरानी बांध परियोजना के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रमुख बिंदु

- सिंचाई सचिव हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में काठगोदाम से 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम में गोला नदी पर जमरानी बांध (150.6 मीटर ऊँचाई) का निर्माण करके इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया जाएगा।
- जमरानी बांध परियोजना को वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत 57065 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई के साथ-साथ हल्द्वानी शहर को वर्ष 2055 तक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है। परियोजना से हर साल 63 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी।
- सचिव ने कहा कि निवेश की मंज़ूरी मिलने के बाद जमरानी बांध परियोजना पर शीघ्र पुनर्वास सहित निर्माण कार्यों को शुरू किया जाएगा।
- विदित है कि 10 जून, 2022 को जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जमरानी बांध परियोजना के लिये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2584.10 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी।
- सिंचाई सचिव ने बताया कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में तय किया गया कि परियोजना के धन आवंटन के लिये जल शक्ति मंत्रालय की ओर से वित्त मंत्रालय एवं केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसमें राज्य को 10 प्रतिशत अंशदान और केंद्र सरकार को 90 प्रतिशत अंशदान देना होगा।
- सिंचाई सचिव ने बताया कि परियोजना से प्रभावितों के पुनर्वास के लिये शीघ्र ही पुनर्वास नीति कैबिनेट की मंज़ूरी हेतु रखी जाएगी और पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की व्यवस्था के अनुसार प्रभावित ग्रामवासियों का सम्यक रूप से पुनर्वास किया जाएगा।

पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल 'ट्रैक ऑफ द ईयर' घोषित

चर्चा में क्यों ?

19 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद (यूटीडीबी) की ओर से बागेश्वर ज़िले के पिंडारी ग्लेशियर और चमोली ज़िले में बागची बुग्याल को 'ट्रैक ऑफ द ईयर' घोषित किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि पिंडारी ग्लेशियर और बागची बुग्याल, दोनों ट्रैकों के लिये दल को रवाना करने हेतु टूर ऑपरेटरों को पर्यटन विभाग की ओर से प्रत्येक ट्रैकर को ट्रैकिंग पर किये जाने वाले कुल खर्च पर दो हज़ार रुपए की सब्सिडी भी दी जाएगी।
- उन्होंने कहा कि विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन और शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये यह ट्रैकिंग कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस ट्रैक के माध्यम से विंटर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन को केदारकांठा की भाँति प्रचारित एवं प्रसारित किया जाएगा तथा ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिये विभाग की ओर से ट्रैकिंग गाइड ट्रेनिंग भी दी जा रही है।
- उल्लेखनीय है कि पिंडारी ग्लेशियर ट्रैक की शुरुआत कुमाऊँ के काठगोदाम से होगी, जो खाती, दव्याली, फुर्किए, ज़ीरो पॉइंट, खाती के बाद खरकिया से होते हुए काठगोदाम में संपन्न होगा। वहीं, बागची बुग्याल के ट्रैक की शुरुआत देहरादून के ऋषिकेश से होगी, जो घेस, देवलीखेत से होते हुए बागची बुग्याल के बेस कैंप में संपन्न होगा। यहाँ से ट्रैकर धुलंब होते हुए बागची के टॉप हिमानी पहुँचेंगे।

प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड में 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया

चर्चा में क्यों ?

21 अक्टूबर, 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीमा पर स्थित उत्तराखंड के माणा गाँव में आयोजित कार्यक्रम में राज्य के लिये 3400 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- इन परियोजनाओं में गौरीकुंड-केदारनाथ और गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब दो नई रोपवे परियोजनाओं सहित दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएँ माणा से माणा पास (एनएच 07) और जोशीमठ से मलारी (एनएच107बी) शामिल हैं।
- केदारनाथ रोपवे लगभग 7 किलोमीटर लंबा होगा, जो गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ेगा, जिससे दोनों स्थानों के बीच यात्रा का समय वर्तमान में 6-7 घंटे से कम होकर लगभग 30 मिनट का रह जाएगा।
- हेमकुंड रोपवे गोविंदघाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा, जो लगभग 4 किलोमीटर लंबा होगा और यात्रा समय को एक दिन से कम करके केवल 45 मिनट तक सीमित कर देगा। यह रोपवे घांघरिया को भी जोड़ेगा, जो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है। इन दोनों रोपवे को लगभग 2430 करोड़ रुपए की संचयी लागत से विकसित किया जाएगा।
- इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह परिवहन का एक पर्यावरण अनुकूल साधन होगा, जो आवागमन को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करेगा। इस अहम बुनियादी ढाँचे का विकास धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को रफ्तार मिलेगी और साथ-ही-साथ रोज़गार के कई अवसर पैदा होंगे।
- कार्यक्रम के दौरान उन्होंने करीब 1000 करोड़ रुपए की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। जिनमें दो सड़क चौड़ीकरण परियोजनाएँ माणा से माणा पास और जोशीमठ से मलारी तक शामिल हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्रों में हर मौसम में सड़क संपर्क प्रदान करने और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के अलावा रणनीतिक दृष्टि से भी फायदेमंद साबित होंगी।
- प्रधानमंत्री ने 'वोकल फॉर लोकल' का ज़िक्र करते हुए देशवासियों से आग्रह किया कि जहाँ भी जाएँ, एक संकल्प करें कि यात्रा पर जितना भी खर्च करते हैं, उसका कम-से-कम 5 प्रतिशत वहाँ के स्थानीय उत्पाद खरीदने पर खर्च करें। इससे इन सारे क्षेत्रों में रोज़ी-रोटी के रास्ते खुल जाएंगे।
- प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा माणा को भारत के अंतिम गाँव की बजाय देश का पहला गाँव कहे जाने पर मुहर लगाते हुए कहा कि पहले जिन इलाकों को देश के सीमाओं का अंत मानकर नज़रअंदाज किया जाता था, हमने वहाँ से देश की समृद्धि का आरंभ मानकर शुरू किया।

नोट :

उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान

चर्चा में क्यों ?

24 अक्तूबर, 2022 को उत्तराखंड के उद्योग निदेशक सुधीर चंद्र नौटियाल ने बताया कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वाराणसी में 16 से 21 अक्तूबर तक आयोजित उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक में उत्तराखंड ने पहला स्थान प्राप्त किया है।

प्रमुख बिंदु

- उत्तर भारत भौगोलिक संकेतांक महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से जीआई पंजीकृत सात उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। इन जीआई उत्पादों में बेरीनाग चाय, ऐपण और प्यूरा उत्पाद आकर्षण का केंद्र रहे।
- राज्य के उद्योग निदेशक ने बताया कि राज्य द्वारा जीआई पंजीकृत कुमांऊ च्यूरा ऑयल, मुनस्यारी रजमा, भोटिया दन, ऐपण, रिंगाल क्राफ्ट, ताम्र उत्पाद व थुलमा समेत अन्य उत्पाद प्रदर्शित किये गए।
- उन्होंने बताया कि भौगोलिक संकेतांक किसी क्षेत्र विशेषता वाले उत्पादों को कानूनी संरक्षण प्राप्त करता है।
- उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 16 से 21 अक्तूबर तक उत्तर भारत जीआई महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें उत्तर के 11 राज्यों की ओर से 100 जीआई उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई।

उत्तराखंड में हिम तेंदुए छह साल में बढ़कर 121 हुए

चर्चा में क्यों ?

23 अक्तूबर, 2022 को विश्व हिम तेंदुआ दिवस के मौके पर उत्तराखंड वन विभाग ने इन्हें लेकर आँकड़े जारी किये। इनके अनुसार राज्य में करीब 121 हिम तेंदुए हैं। 2016 में एक ऑकलन के दौरान इनकी संख्या 86 के आसपास थी।

प्रमुख बिंदु

- वन विभाग के आँकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में हिम तेंदुओं (Snow leopard) का कुनबा बढ़ रहा है, जो कि जैव-विविधता के लिहाज से शुभ संकेत है। स्नो लेपर्ड दुनिया के सबसे खूबसूरत और दुर्लभ जीवों में से एक है। राज्य में लंबे समय से हिम तेंदुओं की गणना और इस दुर्लभ जीव को संरक्षित करने के प्रयास चल रहे थे, इन कोशिशों के सफल नतीजे भी अब देखने को मिले हैं।
- चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन समीर सिन्हा ने बताया कि राज्य में हिम तेंदुए के लिये उपलब्ध क्षेत्रफल के 12764.35 वर्ग किमी. का सर्वे किया गया है। यह गिनती 2 चरणों में पूरी हुई। इसमें गोविंद राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव विहार, केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग, नंदा देवी बायोस्फियर के उच्च स्थलीय क्षेत्र तथा उत्तराखंड के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र शामिल किये गए।
- इस वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार उत्तराखंड में हिम तेंदुओं की अनुमानित संख्या 121 आँकी गई। हिम तेंदुए राज्य के 3000 मीटर की ऊँचाई वाले हिमालयी क्षेत्र में रहते हैं। कैमरा ट्रैप में हिम तेंदुओं की गतिविधियां अक्सर नज़र आती हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की नेलांग वैली में भी हिम तेंदुओं, यानी स्नो लेपर्ड को कई बार देखा गया है।
- हिम तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा अनकिया (Panthera uncia) है। हिम तेंदुआ खाद्य श्रृंखला में शीर्ष शिकारी के रूप में अपनी स्थिति के कारण पहाड़ के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य के एक संकेतक के रूप में कार्य करता है।
- हिम तेंदुए को IUCN की विश्व संरक्षण प्रजातियों की रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा यह लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट-I में भी सूचीबद्ध है। यह भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची-I में सूचीबद्ध है।
- भारत सरकार ने हिम तेंदुए की पहचान उच्च हिमालय की एक प्रमुख प्रजाति के रूप में की है। भारत वर्ष 2013 से वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण (GSLEP) कार्यक्रम का हिस्सा है।
- अक्तूबर 2020 में हिम तेंदुओं की रक्षा के लिये 'हिमालय संरक्षक' नामक एक सामुदायिक स्वयंसेवक कार्यक्रम शुरू किया गया था।
- वर्ष 2019 में 'स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट' पर फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल भी लॉन्च किया गया, जो इसकी आबादी की निगरानी के लिये बहुत उपयोगी है।

नोट :

- वर्ष 2009 में हिम तेंदुओं और उनके निवास स्थान के संरक्षण के लिये एक समावेशी एवं सहभागी दृष्टिकोण को बढ़ावा देने हेतु 'हिम तेंदुआ परियोजना' शुरू की गई थी।
- हिम तेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम पँजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि मध्य एशिया के पहाड़ी परिदृश्य में हिम तेंदुआ का एक विशाल, लेकिन खंडित वितरण है, जो हिमालय के विभिन्न हिस्सों, जैसे- लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम को कवर करता है।
- हिम तेंदुए उन ऊँचे पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो 18,000 फीट की ऊँचाई पर हैं, ज़्यादातर इस तरह के क्षेत्र हिमालय में हैं। चीन और मंगोलिया में हिम तेंदुओं की संख्या सबसे अधिक है। वे नेपाल, भारत, पाकिस्तान और रूस में भी पाए जाते हैं।
- गौरतलब है कि 23 अक्तूबर, 2013 को हिम तेंदुए के संरक्षण पर पहले वैश्विक मंच के दौरान बिश्केक घोषणा को अपनाया गया था। फोरम किर्गिजस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित किया गया था। वर्ष 2014 में, बिश्केक घोषणा की एक साल की सालगिरह मनाने के लिये, मंच पर मौजूद बारह देशों ने 23 अक्तूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस घोषित किया।

लैंसडौन का नाम बदलकर 'कालौं का डांडा' रखने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उत्तराखंड के पौड़ी ज़िले में स्थित 132 साल पुराने लैंसडौन छावनी ने लैंसडौन का नाम 'कालौं का डांडा (काले बादलों से घिरा पहाड़)' रखने का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा है।

प्रमुख बिंदु

- रक्षा मंत्रालय के आर्मी हेड कवार्टर ने सब एरिया उत्तराखंड से ब्रिटिशकाल में छावनी क्षेत्रों की सड़कों, स्कूलों, संस्थानों, नगरों और उपनगरों के रखे नामों को बदलने के लिये प्रस्ताव मांगे हैं।
- रक्षा मंत्रालय ने उनसे ब्रिटिशकाल के समय के नामों के स्थान पर क्या नाम रखे जा सकते हैं, इस बारे में भी सुझाव देने को कहा गया है। इसी के तहत लैंसडौन छावनी ने इसका नाम 'कालौं का डांडा' रखने का प्रस्ताव भेजा है। पहले इसे 'कालौं का डांडा' पुकारा जाता था। स्थानीय लोग इसका नाम यही रखने की मांग वर्षों से करते आए हैं। रक्षा मंत्रालय को भी इस बाबत कई पत्र भेजे जा चुके हैं।
- गौरतलब है कि 1886 में गढ़वाल रेजीमेंट की स्थापना हुई थी। 5 मई, 1887 को लेखकर्नल मेरविंग के नेतृत्व में अल्मोड़ा में बनी पहली गढ़वाल रेजीमेंट की पलटन 4 नवंबर 1887 को लैंसडौन पहुँची थी। उस समय लैंसडौन को 'कालौं का डांडा' कहते थे। 21 सितंबर, 1890 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडौन के नाम पर इसका नाम लैंसडौन रखा गया।

जमरानी बांध से पहले बनेंगे दो कॉफर बांध

चर्चा में क्यों ?

24 अक्टूबर, 2022 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार बहु-उद्देशीय जमरानी बांध के निर्माण से पहले दो कॉफर बाँध और दो टनल बनाई जाएंगी। 600 मीटर की दो टनलों के ज़रिये गौला नदी का पानी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- जमरानी बांध के लिये वित्त मंत्रालय से स्वीकृति मिलने का इंतज़ार है। सिंचाई विभाग ने बांध के निर्माण के लिये एडवांस टेंडर आमंत्रित किये हैं। 1828 करोड़ रुपए की लागत से कॉफर बांध, टनल, एप्रोच रोड आदि कार्य किये जाएंगे।
- विदित है कि उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में गोला नदी पर बहु-उद्देशीय जमरानी बांध परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना के प्रथम चरण में गोला बैराज का निर्माण, 244 किमी. नहर का पुनर्निर्माण और दामुवा एवं अमृतपुरी कॉलोनी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरे चरण में मुख्य बांध के निर्माण पर विचार किया जा रहा है।

नोट :

- जमरानी बांध क्षेत्र में 20 लाख घनमीटर के दायरे में कंक्रीटेशन का कार्य किया जाना है। इसके लिये दो डायवर्जन टनल और दो कॉफर डैम बनाए जाने हैं। 600 मीटर की दो टनलों के ज़रिये नदी का पानी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुँचाया जाएगा। सिंचाई विभाग ने इस पूरा खाका तैयार कर लिया है। पहाड़ी के बीच से होते हुए ये टनल गुज़रेगी।
- गौरतलब है कि कॉफर बांध ऐसा स्थायी ढाँचा है, जिसे एक बड़े जलीय क्षेत्र को जलरहित करने के लिये बनाया जाता है, जिससे वहाँ निर्माण कार्य किया जा सके। इसके ज़रिये नदी के प्रवाह को सुरंग के माध्यम से वैकल्पिक मोड़ दिया जाता है। आमतौर पर दो कॉफर डैम बनाए जाते हैं- अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम कॉफर डैम। जब नदी तल में संरचना का निर्माण करना हो, तब ये बांध बनाए जाते हैं। बांध और संबंधित संरचनाओं का निर्माण पूरा होने पर डाउनस्ट्रीम कॉफर को हटा दिया जाता है और अपस्ट्रीम कॉफर बांध में पानी भर दिया जाता है।

केंद्र ने उत्तराखंड के हवाले की एचएमटी की 45.33 एकड़ ज़मीन

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित एचएमटी की बहुप्रतीक्षित 33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित कर दी। मंत्रालय ने भूमि हस्तांतरण के आदेश जारी कर दिये हैं।

प्रमुख बिंदु

- आदेश के अनुसार रानीबाग और हल्द्वानी स्थित एचएमटी की 33 एकड़ भूमि उत्तराखंड सरकार को 72 करोड़ दो लाख 10 हज़ार रुपए की रिज़र्व प्राइज़ पर हस्तांतरित की गई है। बाज़ार दर पर भूमि की बहुत अधिक लागत है।
- गौरतलब है कि राज्य सरकार कई वर्षों से भूमि प्राप्त करने के लिये केंद्र सरकार से अनुरोध कर रही थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भूमि हस्तांतरित करने का अनुरोध किया था। साथ ही, अगस्त में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडेय के साथ बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था।
- एचएमटी की भूमि पर राज्य सरकार मिनी सिडकुल का निर्माण कर सकती है। राज्य में बड़ी संख्या में उद्यमी निवेश करने के इच्छुक हैं, लेकिन सरकार के सामने उद्योगों के लिये भूमि की व्यवस्था करना बहुत बड़ी चुनौती है।

महिला क्षैतिज आरक्षण के अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार, राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद होगा लागू

चर्चा में क्यों ?

27 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के कार्मिक एवं सतर्कता सचिव शैलेश बगौली ने मीडिया को बताया कि राज्य की महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण के लिये अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। अगले हफ्ते ड्राफ्ट विधायी विभाग को भेजा जाएगा, वहाँ से राज्यपाल की मंज़ूरी के लिये राजभवन भेजा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सचिव शैलेश बगौली ने बताया कि उत्तराखंड की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के लिये अध्यादेश का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। राज्यपाल की मंज़ूरी के बाद राज्य में महिला क्षैतिज आरक्षण का कानून बन जाएगा।
- विदित है कि नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा महिला क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश पर रोक लगाने के बाद राज्य सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया। क्षैतिज आरक्षण बहाल कराने के लिये पिछले दिनों प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश लाने पर सहमति बनी थी।
- शैलेश बगौली के मुताबिक प्रदेश सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण बहाल कराने के लिये भी शासन स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। इस संबंध में न्याय विभाग से विचार-विमर्श चल रहा है। क्षैतिज आरक्षण के समर्थन में ठोस विधिक आधार तैयार करने के बाद प्रस्ताव न्याय विभाग को भेजा जाएगा।
- गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण के शासनादेश को निरस्त कर दिया था।
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर राज्यपाल लेख जख गुरमीत सिंह (सेनिख) ने राजभवन में कई वर्षों से लंबित राज्य आंदोलनकारी क्षैतिज आरक्षण विधेयक को लौटा दिया। इस विधेयक के लौटने के बाद सरकार से क्षैतिज आरक्षण के लिये तात्कालिक तौर पर अध्यादेश या विधेयक लाने की मांग की गई।

नोट :

रक्षामंत्री ने चमोली-उत्तरकाशी में किया चार मोटर पुलों का वर्चुअल उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

28 अक्टूबर, 2022 को रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र चमोली और उत्तरकाशी के नेलांग घाटी में चार मोटर पुलों का वर्चुअल उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- रक्षामंत्री ने राज्य के कुलसारी में कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे पर तीन और नेलांग में एक पुल का उद्घाटन किया है और इन पुलों के बनने से भारत-चीन सीमा तक सेना की आवाजाही सुगम हो सकेगी तथा इसके अलावा सेना के बड़े वाहन आसानी से सीमा तक जा सकेंगे।
- विदित है कि राज्य में कर्णप्रयाग-ग्वालदम हाईवे पर तीनों पुलों का निर्माण बीआरओ के 66 आरसीसी कमान गौचर की ओर से किया गया है। कुलसारी में हाईवे पर बने पुल की लंबाई 50 मीटर, थराली में कुसेरी पुल की 40 मीटर और लोल्टी में बने पुल की लंबाई 35 मीटर है।
- उत्तराखंड में शिवालिक प्रोजेक्ट के चीफ इंजीनियर बिग्रेडियर राजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सीमा सड़क संगठन ने इन तीन पुलों का निर्माण मात्र डेढ़ साल में किया है।
- राज्य के उत्तरकाशी ज़िले के सीमांत क्षेत्र नेलांग घाटी में सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण पागल नाला पर पुल निर्माण कार्य पूरा हो गया है तथा अब भारी बरसात और भूस्खलन से नेलांग घाटी सड़क बंद नहीं होगी।
- बीआरओ के मेजर नमन नरूला ने बताया कि यह पुल सेना के सर्वाधिक भार वाले टैंकों व उपकरणों को ले जाने में समर्थ है। सेना की तकनीकी भाषा में इसकी भार वहन क्षमता 70 आर है।
- नेलांग घाटी में भू-स्खलन प्रभावित क्षेत्रों में चार और पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे बरसात के दौरान भूस्खलन के चलते सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण सड़क बंद न हो। ये सभी पुल 50 से 65 मीटर स्पान के हैं। प्रत्येक पुल की लागत 6 से 7 करोड़ रुपए है तथा इनमें से एक पुल का निर्माण कार्य अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। ये सभी पुल भैरवघाटी से नेलांग घाटी के बीच 25 किमी के दायरे में बन रहे हैं।
- राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में इन पुलों के साथ ही देश की 72 अन्य परियोजनाओं का भी लेह घाटी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये लोकार्पण किया।

उत्तराखंड में बदले जाएंगे गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम

चर्चा में क्यों ?

29 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया कि राज्य में उपनिवेशवाद, यानी गुलामी के सभी प्रतीकों के नाम बदले जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिया है कि राज्य में उपनिवेशवाद के सभी प्रतीकों का नाम बदलकर उनका दोबारा नामकरण किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में जिन सड़कों और शहरों के नाम अंग्रेज़ों के जमाने के हैं, उनको बदला जाएगा।
- विदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद देश में उपनिवेशवाद के सभी प्रतीकों को बदला जा रहा है और इन्हीं की तर्ज़ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने सूबे में कई स्थानों के नाम बदले हैं।
- गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण करने के साथ ही 'कर्त्तव्य पथ' का उद्घाटन किया था। 'कर्त्तव्य पथ' को पहले 'राजपथ' कहा जाता था।

नोट :

उत्तराखंड की 10 महिलाओं को मिलेगा नंदा देवी वीरता सम्मान

चर्चा में क्यों ?

30 अक्टूबर, 2022 को उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण की अध्यक्षता में गठित चयन समिति ने वीरता और साहस दिखाने वाली राज्य की 10 महिलाओं को 'नंदा देवी वीरता सम्मान'प्रदान किये जाने की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि श्री नंदा देवी राजजात पूर्व पीठिका समिति की ओर से हर साल अलग-अलग क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाता है।
- इस साल वीरता और साहस के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान देने वाली पर्वतीय क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में कार्यरत् महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। इन्हें एक नवंबर को राज्य विधानसभा के प्रकाश पंत भवन सभागार में आयोजित होने वाले समारोह में सम्मानित किया जाएगा।
- इन महिलाओं में राज्य के पौड़ी से फ्लाइंग ऑफिसर निधि बिष्ट, बागेश्वर से अनीता टम्टा, पिथौरागढ़ के धारचूला की कलावती बडाल, चंपावत की तारा जोशी, कपकोट की तारा टाकुली, तारा पांगती, पिथौरागढ़ से गीता देवी पांगती, बागेश्वर से आशा देवी, चंबा से निवेदिता पंवार, पिथौरागढ़ से सीता देवी बुरफाल को सम्मान के लिये चयनित किया गया है।

दृष्टि The Vision

नोट :